जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

भारत में पेसा की स्थिति

एक ग्रामवासी के नजरिये से

मिलिंद थट्टे

निदेशक, टीईईआर (जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान) फाउंडेशन

प्राकृतिक गांव और उसकी विधानसभा

वांगडपाडा ग्रामसभा (जि. पालघर)

- गांव पीढ़ियों से है
- प्रकृति के कारण एकजुट
- रिश्तेदारी और विश्वास के कारण एकजुट

- पेसा की धारा 4 (ख) इसे मान्यता देती है

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

इसे गांव को क्यों दें?

- सहमति से सरकार
- प्राकृतिक विकास द्वारा अर्जित विश्वास
- प्रत्यक्ष और बुनियादी परस्पर निर्भरता
- लोकतंत्र मतपत्र से भी गहन

एक स्वदेशी स्थानीय सरकार के अंश जो अभी भी भारतीय ग्रामीण जीवन में पाए जाने बाकी हैं, मुझे रुचि और सुझाव से भरे हुए लगते हैं। वे हैं, यह शायद ही कहा जाना चाहिए, आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। मध्य भारत में लंबे समय तक सेवा करने वाले एक सक्षम कलेक्टर ने मुझे सूचित किया कि वह कुछ महीने पहले तक इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिन गांवों पर उन्होंने शासन किया था, उनमें से किसी में भी इस तरह का कुछ भी मौजूद था। लेकिन इस विषय पर विशिष्ट पूछताछ करने के लिए नेतृत्व किए जाने पर, उन्होंने गांव-गांव में एक या दूसरे रूप में एक स्पष्ट रूप से प्रभावी, कुछ हद तक छायादार, स्थानीय संगठन की खोज की थी, जो वास्तव में, अब सांप्रदायिक चिंता के मामलों पर निर्णय दे रहा था, नागरिक विवादों का फैसला कर रहा था, और यहां तक कि अपराधियों को क्षतिपूर्ति और जुर्माना देने की निंदा कर रहा था। इस तरह का एक स्थानीय सरकारी संगठन, निश्चित रूप से, "अतिरिक्त-कानूनी" है, और इसका कोई वैधानिक वारंट नहीं है, और, ब्रिटिश न्यायाधिकरणों की नजर में, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यह चुपचाप मौजूद है, संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना में अधिक समय तक, और अभी भी प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, केवल आम सहमति से और स्थानीय जनमत की वास्तविक मंजूरी के साथ।

विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया - जॉन मथाई 1915, आमुख प्रोफेसर सिडनी वेब द्वारा प्रस्तावना

उदाहरण के लिए, फ्रांस की तरह इंग्लैंड में, हम अभी भी आदतन लोकतंत्र को प्रतिनिधियों या शासकों के लोकप्रिय चुनाव के रूप में या कम से कम आवश्यक रूप से शामिल मानते हैं: रूसी मीर की तरह भारतीय गांव हमें याद दिला सकता है कि प्रशासन को सार्वजनिक नियंत्रण में लाने के लिए मतपत्र और पार्टी सरकार द्वारा वोट कई समीचीनों में से केवल दो हैं। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में हम बहुमत से निर्णय लेने के बारे में बहुत कुछ करते हैं: भारतीय गांव हमें क्वेकर बैठक की तरह, संभवतः एक उच्च विकल्प प्रदान करता है, अगर हम सरकार में सहमति से, समुदाय की सामान्य भावना से निर्णय में विश्वास करते हैं।

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

ग्राम सभा में विचार-विमर्श और विधान

- छोटी आबादी, बेहतर चर्चा
- एजेंडा लोगों द्वारा
- स्थानीय अध्यक्ष
- स्थानीय भाषा में विचार-विमर्श
- सभी की बात सुनी जायेगी

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

किसी गांव की घोषणा/अधिसूचना

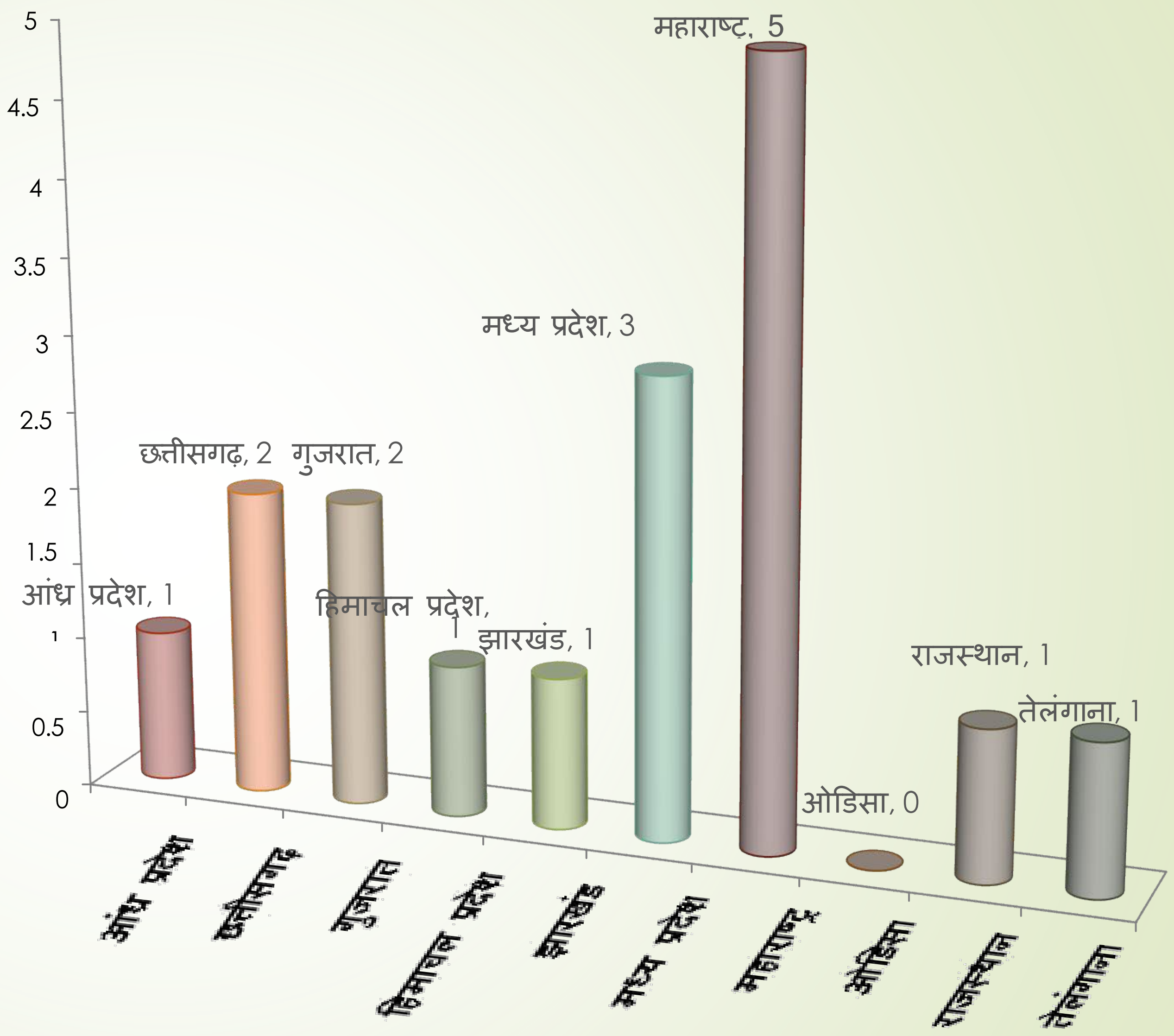

फला/फाल्या/गांव सरकार को दिखाई ही ना दें तो?

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

ग्राम सभा अध्यक्ष

मुख्यमंत्री ही विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, तो कैसा रहेगा?

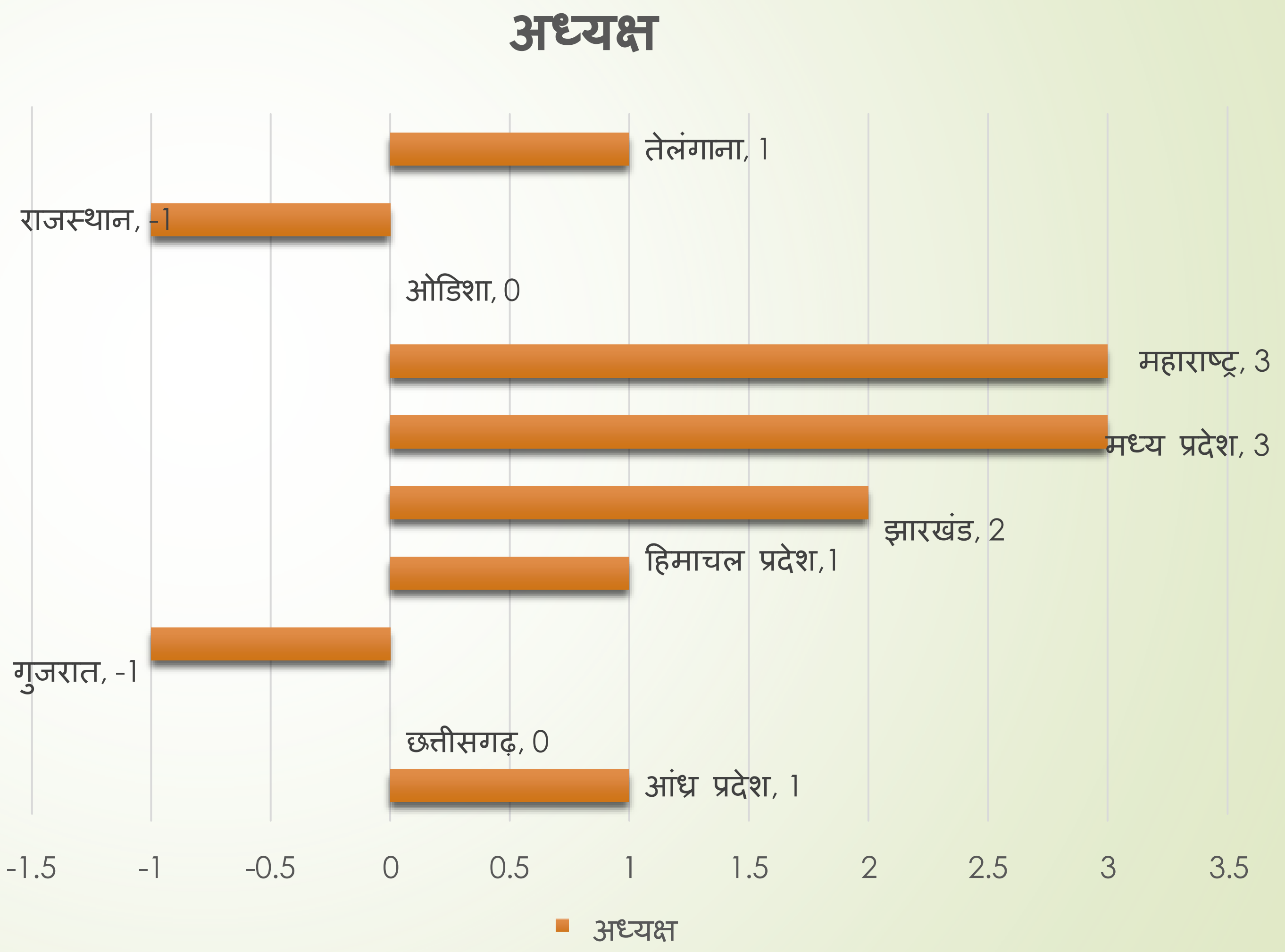

वही व्यक्ति जो ग्राम सभा सरपंच के रूप में काम कर रहा है, अधिकृत कर रहा है और यूसी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

ग्राम सभा सचिव

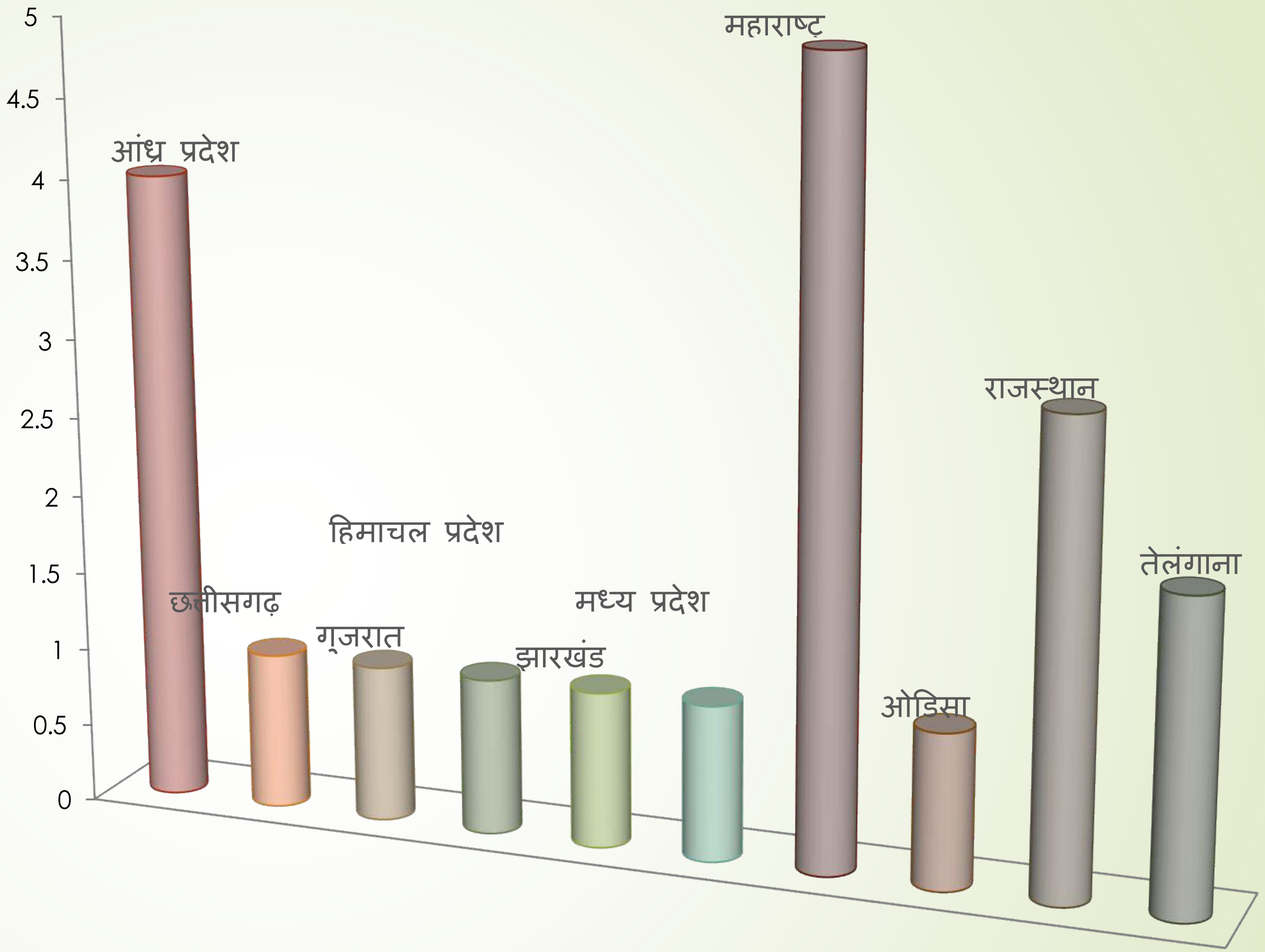

अगर वह नहीं आया तो?

आंध्र प्रदेश: सचिव 5 वर्ष के लिए निर्वाचित, एमएच अल्ट, आरजे: बीडीओ नियुक्त करेंगे

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

ग्राम सभा की बैठकें

जब सचिव चाहेगा तब, या लोग चाहेंगे तब?

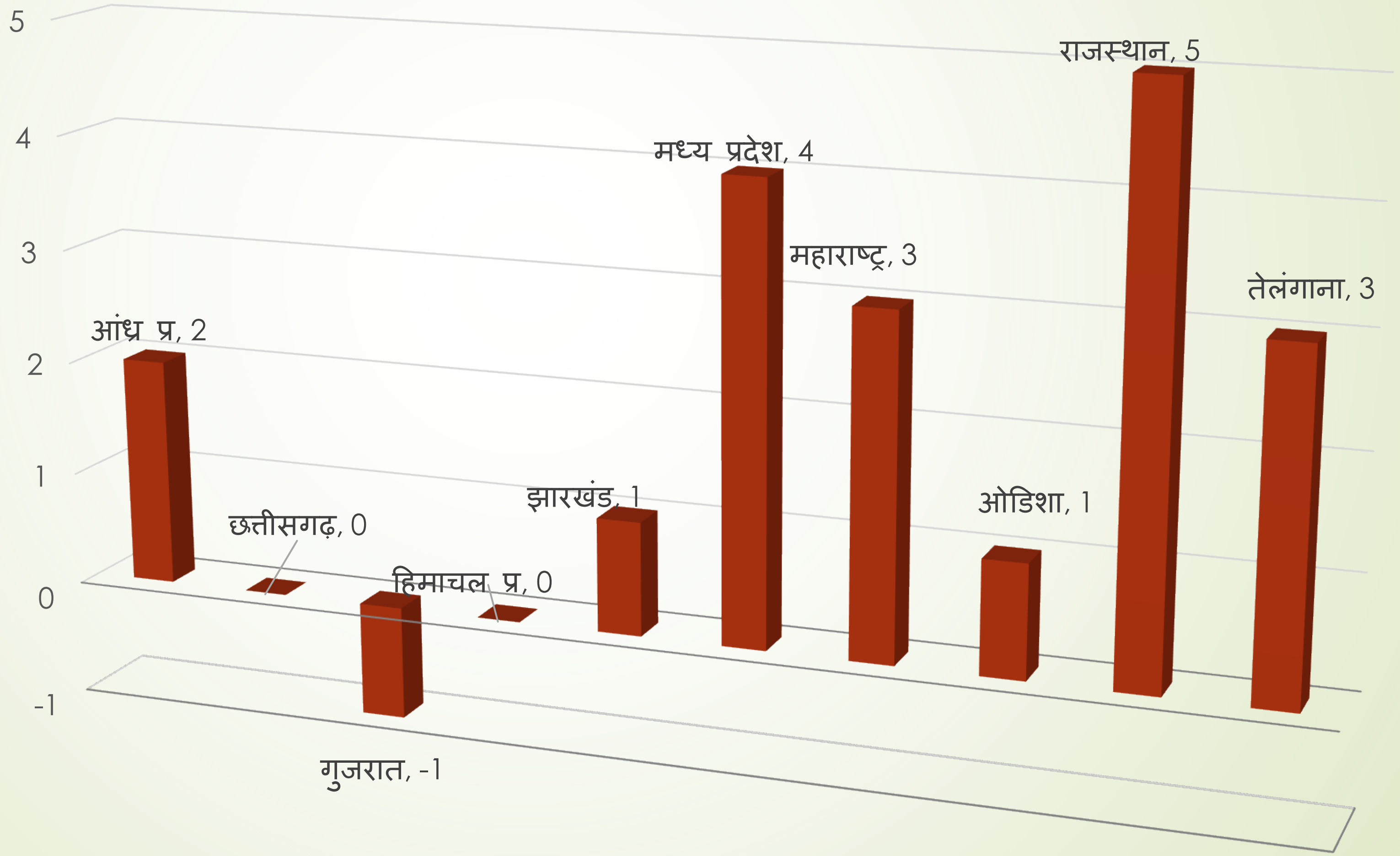

आरजे: 1) सभी तिथियों को पहले से तय करना, 2) 5% सदस्यों द्वारा अनुरोध

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

समितियों का गठन

सचमुच काम करना है क्या?

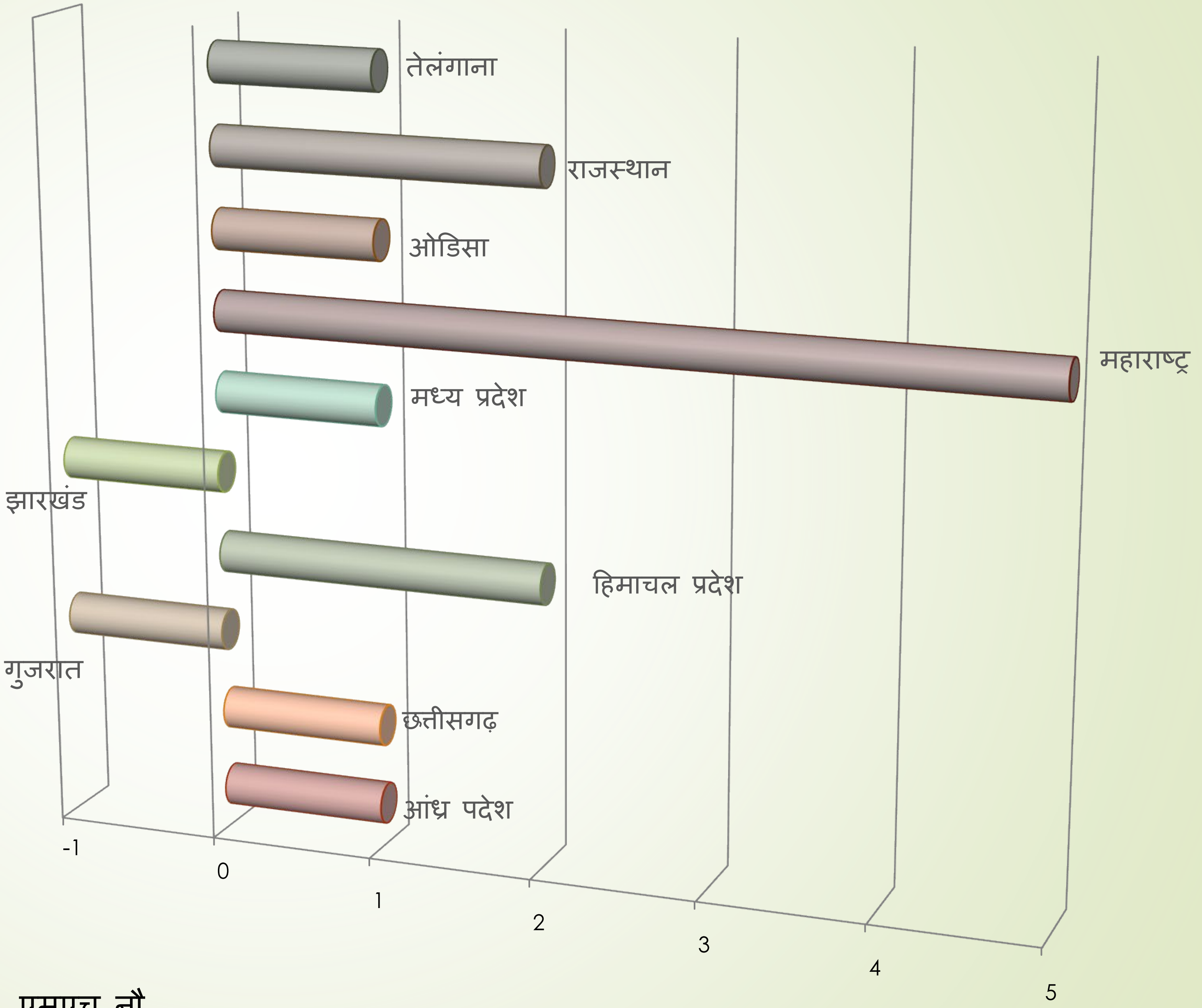

आरजे शांति समिति, एचपी आरएमपीसी, एमएच नौ

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

जल निकायों का प्रबंधन

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

लघु वनोपज का स्वामित्व

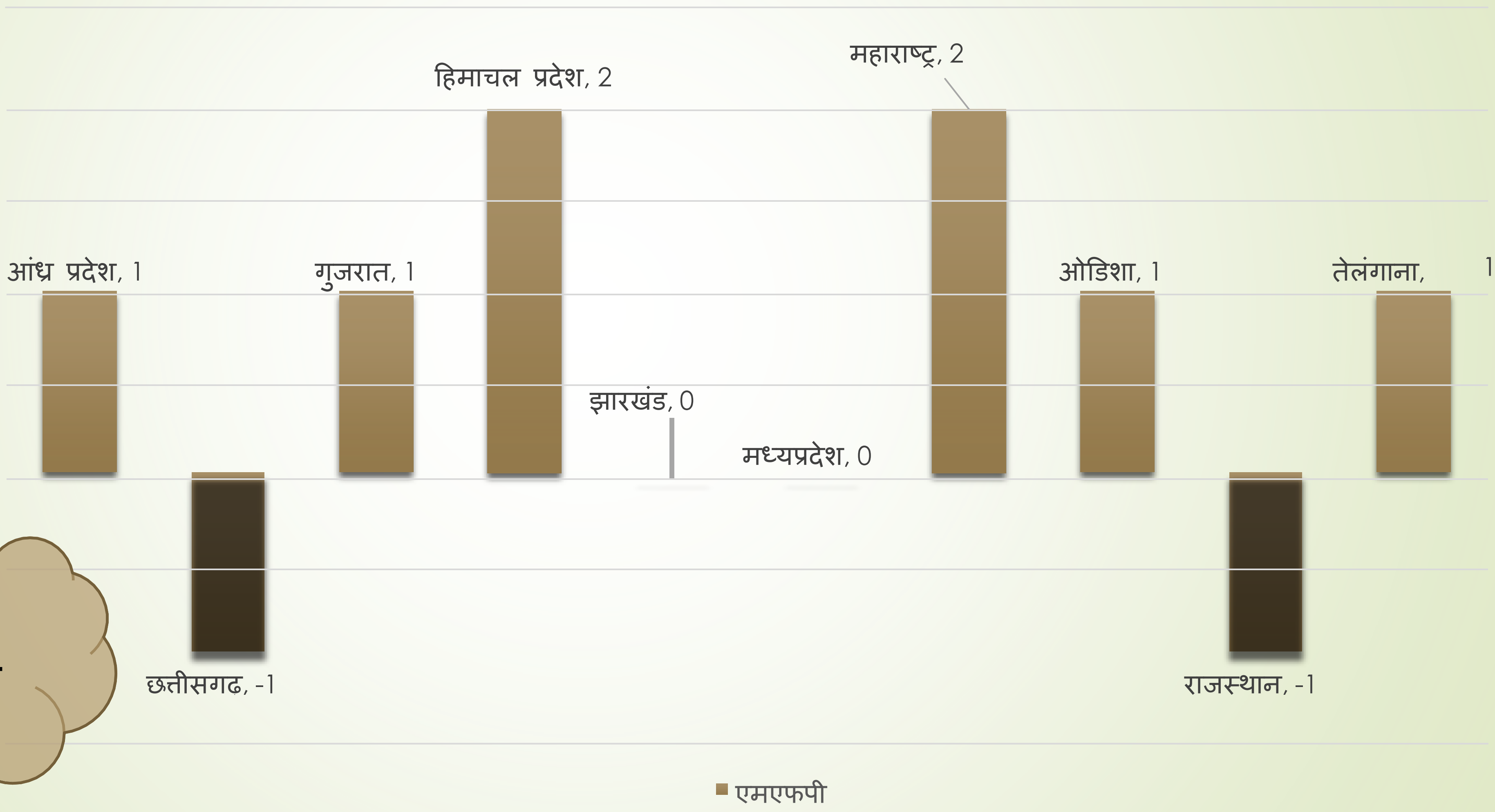

मालिक है लेकिन हाथ बंधा हुआ?

बहिष्करण: एपी बांस + तेंदू, जीजे नेशनल पार्क सैंक्टुरारी, आरजे बांस, तेंदू, घास, एनपी सेंचुरी, सीएच फेडरेशन का स्वामित्व, एमपी अन्य सभी कानून

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

भूमि प्रबंधन

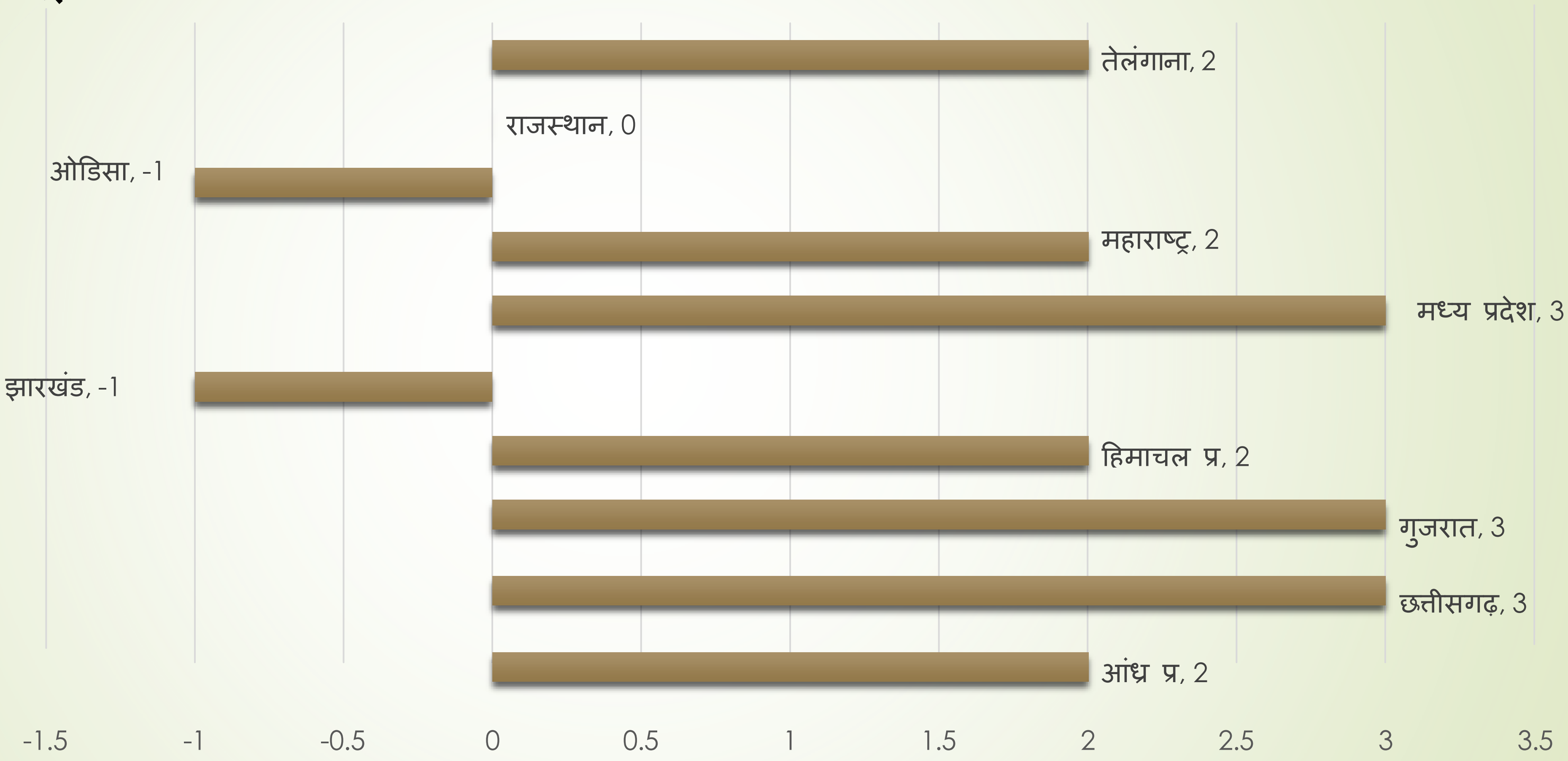

अधिग्रहण: एपी में मंडल पीपी के साथ परामर्श, जिला परिषद में ओडी परामर्श, जीएस की पूर्व सहमति

जीजे भूमि रिकॉर्ड पढ़ना, एपी विस्तृत प्रक्रिया, सीएच एसडीओ कार्रवाई करने के लिए, एचपी जीएस हस्तांतरण के लिए अनुमति

भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए टीएस विस्तृत प्रक्रिया

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

गौण खनिज

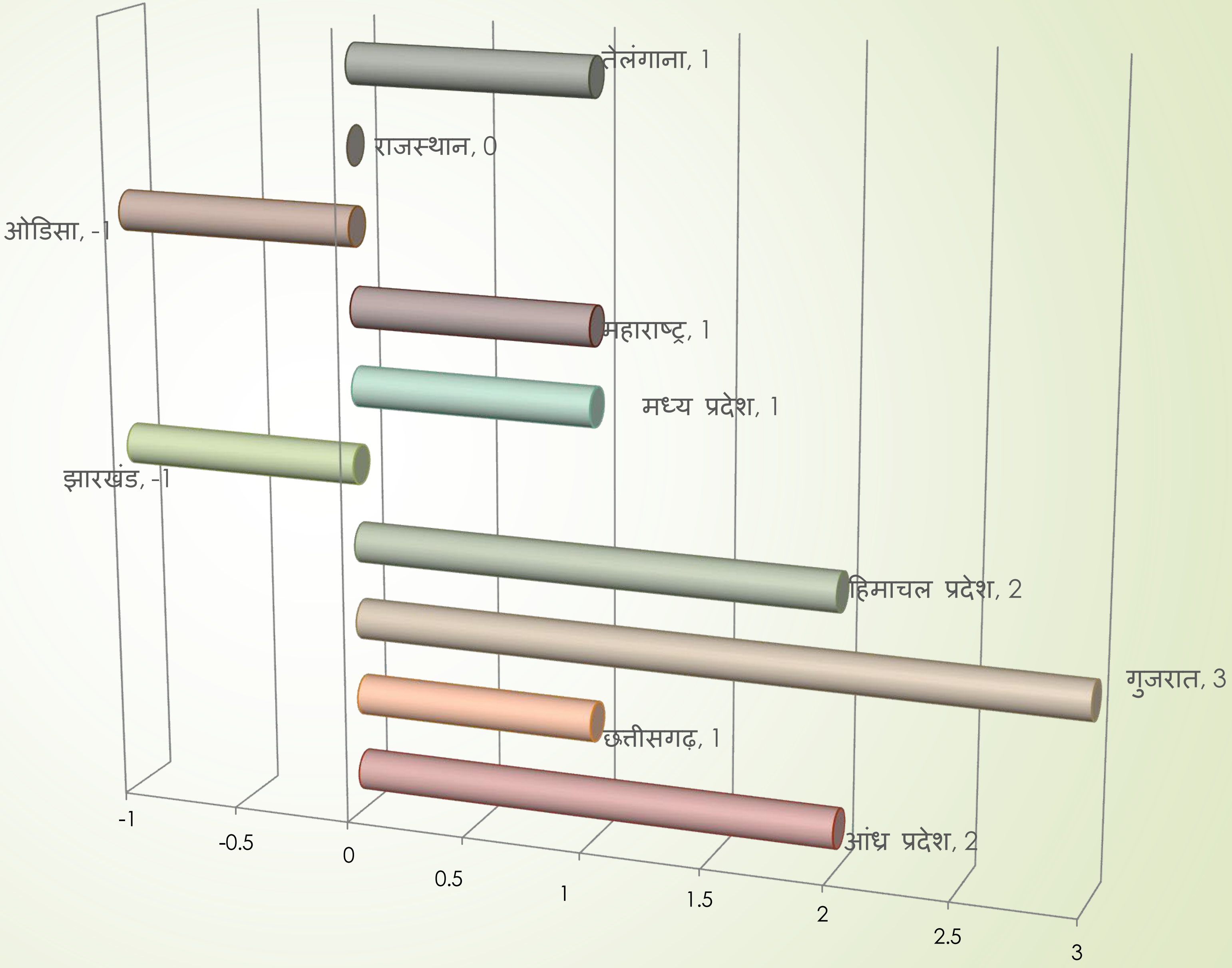

जीजे में सभी खुदाई के लिए जीएस अनुमोदन अनिवार्य, हिमाचल प्रदेश में रॉयल्टी से पंचायत निधि, केवल एसटी-सोसाइटी आंध्र प्रदेश में खनन कर सकती हैं

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

मादक द्रव्यों पर नियंत्रण

- कच्चे माल, उत्पादन, बिक्री खरीद
- लाइसेंस का नवीनीकरण न होना
- नियमों की विविधता

पुढारी

रोजपाडात दारूबंदीचा निर्णय

महिलांचा पुढाकार, दारूबंदीसाठी प्रभातफेरी काढून जनजागृती

जव्हार: पुढारी वृत्तसेवा

दादरानगर हवेली सिल्वासा या केंद्र शासित प्रदेशाला लागून असलेल्या जव्हार तालुक्यातील तलासरी ग्रामपंचायत हद्दीतील रोजपाडा हा सिल्वासा या केंद्र शासित प्रदेशाला लागून असल्याने या पाड्यात रोजच दारूचे अड्डे चालविले जात होते. तसेच रोजच दमण दारूची बिक्री केली जायची, तसेच या दारू बंदीमुळे अनेकांचे संसार उद्धवस्त झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र वयंम चळवळीच्या सहकार्यामुळे गावातील महिलांनी दारू बंदीचा ठोस निर्णय घेत, रोजपाड्यात दारू बंदीची घोषणा देत, प्रभात फेरी काढून दारू बंदीची जनजागृती करण्यात आली.

रोजपाडा गावात ७२ आदिवासी राहत कुटुंब असून, या पाड्यात दारूमुळे दारूडयांनी हैदोस घातला होता. दारूमुळे वाद निर्माण होवून, रोजच गावात भांडण व्हायची. मात्र वयंम चळवळीच्या नेतृवाखाली पेसा गावं घोषित करून, गावात मीटिंग घेण्यात आली. या सभेत दारू बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष करून दारू बंदीसाठी महिलांनी पुढाकार घेवून, रोजपाड्यात रोज पाडणाऱ्या दारू बंदीचा निर्णय घेतला आहे. रोजपाड्यातील ७० ते ८० आदिवासी महिलांनी गावात प्रभात फेरी काढून, दारू बंदीची जनजागृती करण्यात आली. या निर्णयात पुरुषही सहभागी झाले होते.

दारू बंदी करतांना गावात शांतात कमिटीची नेमणूक करण्यात आली आहे. रोजपाड्यातील महिलांचे कौतुक होत आहे. दारूबंदी अन्य निर्णयासाठी नेमण्यात आलेली कमेटीचे अध्यक्ष सुमन बोंबा, उपाध्यक्ष आसम्या रोज, प्रमिला पागी, संजू रोज, रुक्षणा रोज, बिजली सुरुय, मीना रोज, पोवनी रोज असा अनेक महिला या कमेटीत असून, त्यात निर्माण घेण्यात आला आहे. रोजपाड्यात दारु बंदीचा निर्णय घेतल्याने या महिलांचे तालुक्यातून कौतुक केले जात आहे.

Virar-Dahanu Shuttle Edition
12 Feb, 2020 Page No. 1
Powered by : erelego.com

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

नशे पर नियंत्रण

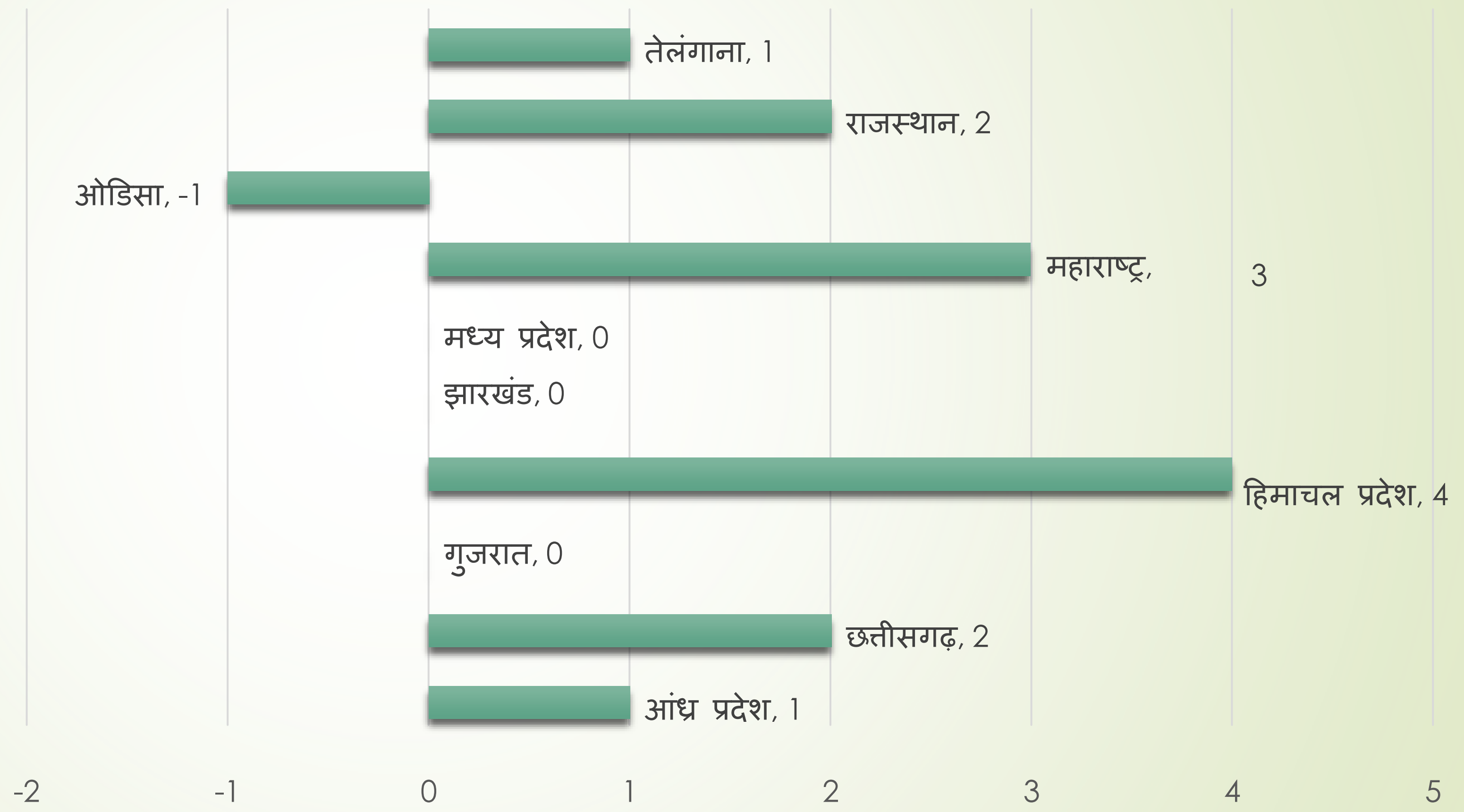

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

पारदर्शिता व उत्तरदायित्व आसान

- सरपंच के अलावा अन्य अध्यक्ष
- लिखित कार्यवाही में प्रशिक्षण
- लेखन व्यय में प्रशिक्षण
- जीएस खर्च में पारदर्शिता
- ग्राम सभा और सरकार से भी यही मांग

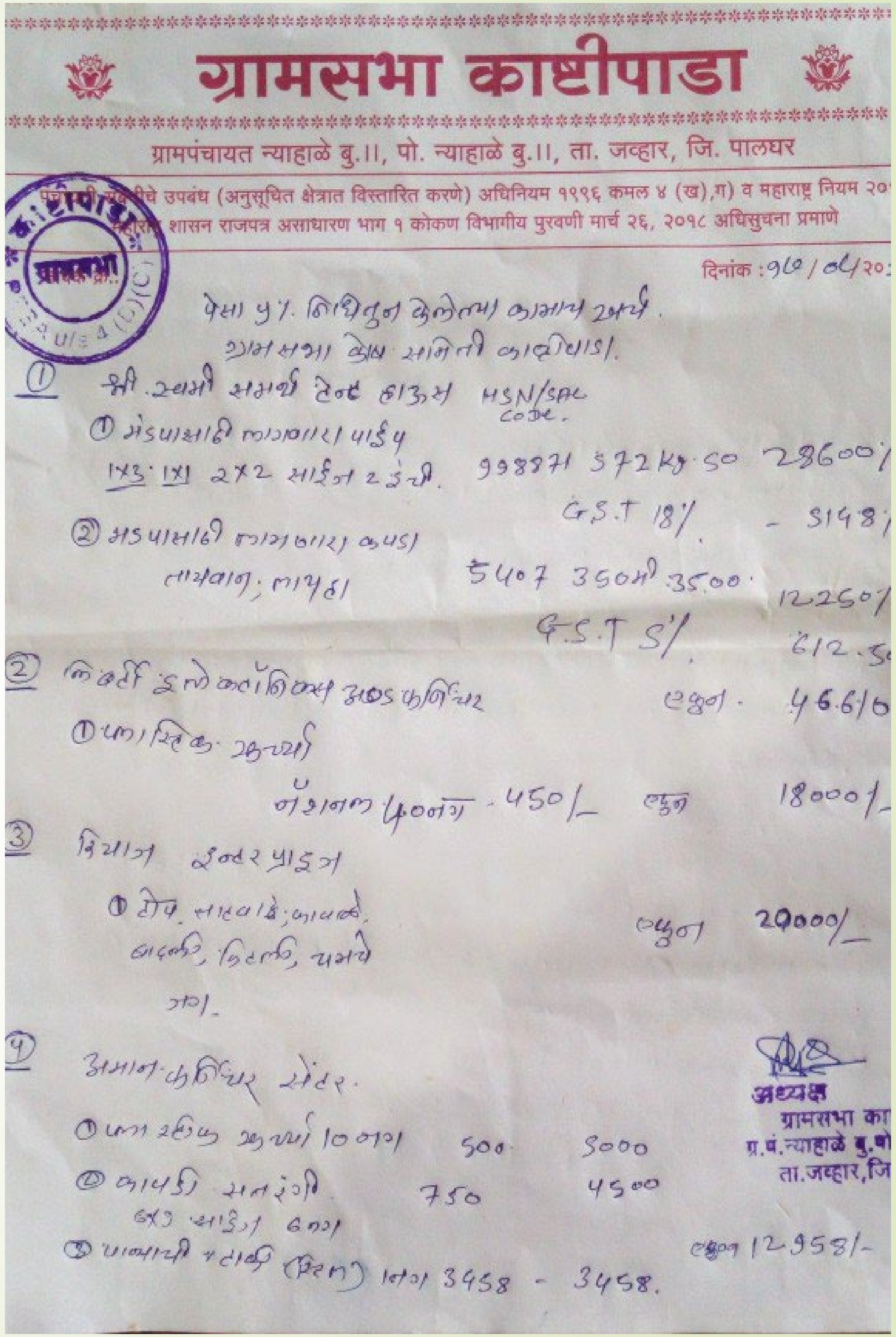
ग्रामसभा काष्टीपाडा
ग्रामपंचायत न्याहाळे बु.।।, पो. न्याहाळे बु.।।, ता. जव्हार, जि. पालघर
दिनांक :

निधियों और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण

- एपी: मंडल पीपी के साथ नियंत्रण (नियम 8 (VI) (i)) टीएसपी पर नियंत्रण ग्रामसभा का उल्लेख नहीं करता है
- उपयोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता: आरजे, एमएच, एपी, जीजे, या
- महाराष्ट्र: 5% टीएसपी निधि को ग्राम सभाओं में अंतरित किया गया

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

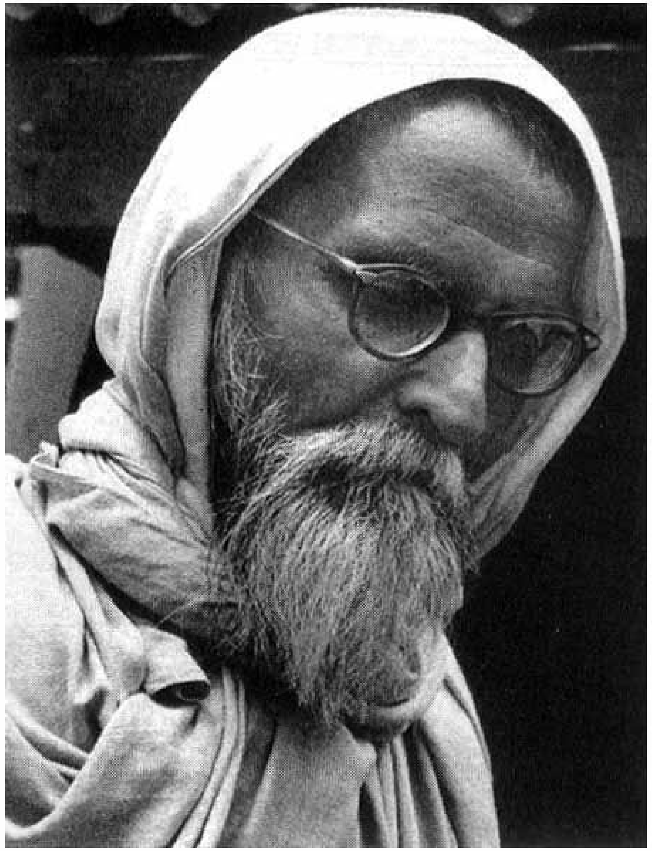

"उन्होंने कहा, 'भारत स्वतंत्र गांवों का एक स्वतंत्र देश था।

मुगल आक्रमण के साथ, हम स्वतंत्र गांवों के साथ एक गुलाम देश बन गए।

ब्रिटिश आक्रमण के साथ, भारत गुलाम गांवों का एक गुलाम देश बन गया।

अंग्रेजों के जाने के बाद, भारत एक स्वतंत्र देश बन गया लेकिन गुलाम गांवों का।

हमें भारत को स्वतंत्र गांवों के साथ एक स्वतंत्र देश बनाने का प्रयास करना चाहिए।"

- विनोबा

जनजातीय लोकाचार और आर्थिक अनुसंधान फाउंडेशन

milindthatte@gmail.com 94215.64330